शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 30 – 7 जुलाई 2025 मूल्य पांच रूपये

# क्या NHAI राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश में कोई निर्माण कर सकता है

## भट्टाकुफर कथित मारपीट प्रकरण से उठी चर्चा

**शिमला/शैल।** शिमला के भट्टाकुफर में एक पांच मंजिला मकान बारिश में गिर जाने के बाद जो राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां निर्मित हुई है उन्होंने न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है। क्योंकि इस मकान के गिरने का कारण राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण की कार्यशैली और कार्य संस्कृति को माना गया है। यहां पर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिये यह प्राधिकरण काम करवा रहा था जिसमें शायद पहाड़ की कटिंग गलत तरीके से की गयी थी जिसके कारण और भी कई भवन खतरे की जद में आ गये हैं। यह क्षेत्र कसुम्पटी विधानसभा में आता है और यहां के विधायक प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। स्वभाविक है कि हर जन प्रतिनिधि ऐसी आपदा में अपने मतदाताओं के संकट में उनके साथ खड़ा होता है और प्रभावित लोग भी सबसे पहले उसी से संपर्क करते हैं। इस स्वभाविक स्थिति में मंत्री मौके का निरीक्षण करने के लिये घटना स्थल पर चले गये। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को भी मौके पर तलब कर लिया। जब यह सारे लोग घटनास्थल पर पहुंच गये तो स्वभाविक रूप से इस त्रासदी से प्रभावितों का रोष और दर्द दोनों ही छलकने ही थे। इसी परिदृश्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जब जनरोष का कोपभाजन का केंद्र बनना पड़ा तो शायद स्थितियां संवाद से निकलकर मारपीट तक भी जा पहुंची। इस मारपीट का गंभीर संज्ञान लेते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्री के निर्देशानुसार अपने मंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली। क्योंकि मंत्री पर भी इस मारपीट में शामिल होने का आरोप लगा है।

हिमाचल में किसी कार्यरत मंत्री के खिलाफ ऐसी एफ.आई.आर. दर्ज होने का यह पहला मामला है। इस प्रकरण में कौन कितना दोषी है अब यह पुलिस जांच का मामला बन गया है इसलिये इस पर इस बिन्दु से कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन यह मामला दर्ज होने के बाद मंत्री से लेकर अन्य तक की जो प्रतिक्रियाएं सामने आयी हैं उन पर टिप्पणियां करना आवश्यक हो जाता है। मंत्री ने इस एफ.आई.आर. को राजनीति से प्रेरित बताते हुये मारपीट में शामिल होने से साफ इन्कार किया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि मारपीट का कोई साक्ष्य है तो उसे सामने लाया जाये। मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रदेश में चल रही कार्यशैली पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाये हैं। यह आरोप है कि प्राधिकरण के ठेकेदार पहाड़ों की अवैज्ञानिक कटिंग कर रहे हैं और वेस्ट को हर कहीं डंप कर रहे हैं। यह भी आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारी और कार्य कर रही कंपनियां किसी की बात नहीं सुनती है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे आरोप अब प्रदेश के हर कोने से आने शुरू हो गये हैं। जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण काम कर रहा है। इन आरोपों से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से ज्यादा तो प्रदेश सरकार और उसकी प्रशासनिक टीम कठघरे में आ रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य प्रदेशों में राजमार्गो और फोरलेन सड़कों के निर्माण का है। लेकिन इन कार्यो में राज्य सरकारों की सहमति और अनुमति के बिना यह प्राधिकरण कुछ नहीं कर सकता यह इसके अधिनियम की बुनियादी शर्त है। इस शर्त के मुताबिक हर निर्माण के लिये प्राधिकरण और राज्य सरकार में एक लिखित अनुबंध होता है। इस अनुबंध के तहत ही इन मार्गो के लिये राज्य सरकारें भूमि का अधिग्रहण करती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। राज्य के सहयोग से ही डी.पी.आर. बनाई जाती है। यदि राजमार्ग के निर्माण में कहीं भी कोई कार्य मानकों के विरुद्ध होता पाया जाता है तो उसका तत्काल संज्ञान स्थानीय संबंधित प्रशासन लेकर राज्य सरकार को अवगत कराता है। राज्य सरकार उसे प्राधिकरण के संज्ञान में लाती है। लेकिन इस समय भट्टाकुफर प्रकरण के बाद जितने आरोप प्रदेश के अलग – अलग हिस्सों से राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण पर लग रहे हैं उसके अनुपात में शायद इससे पहले कोई शिकायतें नहीं रही है। माना यह जाता है कि प्राधिकरण के अधिकारी और कार्य निष्पादन कर रही कंपनियों के ठेकेदारों और राज्य प्रशासन के संबद्ध अधिकारियों और स्थानीय नेतृत्व सभी में एक गहरा गठजोड़ रहता है। प्राधिकरण अपनी इच्छा से राज्य सरकार की अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकता है। इस तरह का लम्बा पत्राचार प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच उपलब्ध है। इस समय प्राधिकरण ने प्रदेश में उन मार्गो के निर्माण से इन्कार कर दिया है जिनकी डी.पी.आर. पिछले तीन वर्षो में नहीं बन पायी है। प्राधिकरण के इस फैसले पर राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देना यही प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार के सहयोग और अनुमति के बिना यह प्राधिकरण राज्य में कुछ नहीं करता है। ऐसे में जब मंत्री ने प्राधिकरण की वर्किंग पर गंभीर आरोप लगाये हैं तो वह आरोप स्वत: राज्य सरकार पर आ जाते हैं। सरकार ने मंत्री पर एफ. आई.आर. करके इस मामले को जितना शान्त करने का प्रयास किया है उन प्रयासों को इस पर उभरी प्रतिक्रियाओं से एक अलग ही कोण उठ खड़ा हुआ है। वैसे मंत्री की प्रतिक्रियाएं भी बहुत हद तक अवांछित हो जाती हैं।

# पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ियों की जांच करेगी सी.आई.डी.

**शिमला/शैल।** हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया है। पिछले सप्ताह बादल फटने की घटना और आस – पास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर पंडोह डैम में एकत्रित हो गई थी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकठ्ठा होने के संभावित कारणों को सामने लाया जायेगा। इस दिशा में सरकार ने अब इस मामले की सीआईडी जांच का फैसला लिया है ताकि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया अमूल्य जीवन बचाना और प्रभावितों को तत्काल बचाव और राहत उपलब्ध करवाना होता है। सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नदी में बह रही लकड़ियां और पंडोह बांध में तैरती हुई लकड़ियों का वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुई हैं। इस विषय में लोगों की चिंता को देखते हुए निरंतर जांच की

शेष पृष्ठ 8 पर.....

# कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की उपलब्धियां सराहनीय:राज्यपाल

**शिमला/शैल।** चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक, शोध व प्रसार कार्यक्रमों व कृषि विस्तार के क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने ये बात पालमपुर में विश्वविद्यालय की 26 वीं सीनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (आई.आर.ए.एफ.) में विश्वविद्यालय ने देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में 13वां स्थान अर्जित किया है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि समर्पित शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की मेहनत का प्रतिफल है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा 182 नई किस्मों का विकास एवं अनुमोदन और 27 स्थानीय किस्मों का पंजीकरण, प्रदेश के किसानों की समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन, स्मार्ट खेती के नए प्रयोग और सटीक कृषि पद्धतियों का प्रसार दर्शाता है कि यह विश्वविद्यालय न केवल अनुसंधान कर रहा है, बल्कि उसे खेत तक पहुंचाने की दिशा में भी सक्रिय है।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक अपने शोध कार्यों को किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित करें। राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के समाधान के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सीमांत क्षेत्रों में ब्लूबैरी जैसी नवाचारपूर्ण फसलें अपनाकर यह दिखाया गया है कि युवा वर्ग खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपना सकता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में,

विश्वविद्यालय में लगभग 60 करोड़ रुपये की 140 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं और 67 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए हैं। यह शोध व नवाचार में वैश्विक सहयोग की दिशा में सशक्त कदम है। इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अनुसंधान, प्रशासन और शिक्षा में कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमारे डेटा निष्पक्ष हों, हमारा दृष्टिकोण पारदर्शी हो और हमारा प्रयास सदैव जनहित में हो।

राज्यपाल ने विश्वास जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र में समग्र विकास का अग्रदूत बना रहेगा। इससे पूर्व, राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में जिंकगो बिलोबा का पौधा भी रोपा।

सीनेट की बैठक के दौरान पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने क्षेत्र में हल्दी की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य योजना तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया।

देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने किसानों को दिए जाने वाले कृषि उपकरणों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की बात कही।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन कुमार ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी सीनेट की बैठक में प्रस्तुत की।

# राज्यपाल ने राहत सामग्री वाहनों को किया रवाना

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से हाल ही में मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर आवश्यक राहत सामग्री से भरे तीन ट्रकों को रवाना किया। यह राहत सामग्री राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से मंडी जिला प्रशासन को भेजी जा रही है ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

आपदा से प्रभावित परिवारों को इस राहत सामग्री में 540 कंबल, 500 तिरपाल शीट, 20 बक्से कपड़े, रसोई सेट, बाल्टियां और अन्य आवश्यक घरेलू सामान शामिल हैं।

राज्यपाल ने थुनाग और आसपास के क्षेत्रों में हुई गंभीर क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन क्षतिग्रस्त सड़कों, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन, सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों द्वारा राहत और बचाव कार्यों में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने लोगों से आग्रह किया कि वह प्रशासन के साथ सहयोग करें और राहत कार्य स्थलों पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को इलाके की बेहतर जानकारी है और जरूरतमंदों तक मदद जल्दी और कुशलता से पहुंचाने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे।

राज्यपाल शुक्ल ने आश्वासन दिया कि रेडक्रॉस के माध्यम से राहत कार्य जारी रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य माध्यमों से भी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद करने का आहवान किया। उन्होंने बारिश के मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने और पर्यटकों से नदी-नालों के करीब न जाने की अपील की।

राज्यपाल ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों के बीच पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधोसंरचना और नीति-निर्माण से जुड़े सभी विभागों से परामर्श करने और राज्य की गंभीर पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक और सतत रणनीति तैयार करने का आहवान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

# सुशासन आदर्श नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण है अब:राज्यपाल

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से संसाधनों का कुशल प्रबंधन, सेवाओं की पारदर्शिता और नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। सुशासन अब केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बन चुका है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल

ने यह बात तपोवन स्थित विधान सभा परिसर में राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र-2 के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही।

उन्होंने राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र-2 की इस महत्वपूर्ण वार्षिक कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के इस पावन स्थल तपोवन में आयोजित यह संवाद निश्चित ही हमारे लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा को और अधिक सशक्त बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह अपार प्रसन्नता का विषय है कि लोक सभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

राज्यपाल ने राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह तथा विभिन्न प्रदेशों से आए सदस्यों का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से देवभूमि आगमन पर स्वागत किया।

राज्यपाल ने कहा कि 30 जून को ''राज्य संसाधनों के प्रबंधन में विधायिकाओं की भूमिका एवं राज्य के विकास'' विषय पर आयोजित विचार-मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र संसाधनों - आर्थिक, प्राकृतिक व मानव संसाधन के न्यायसंगत, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की दिशा तय करने वाली संस्था है।

उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसाधन सीमित हैं और अपेक्षाएं अनंत। ऐसे में विधायिकाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बजट, नीतियों और योजनाओं के निर्माण एवं निगरानी में सकारात्मक, दूरदर्शी और जनहितकारी भूमिका निभाएं।

राज्यपाल ने कहा कि आज ''दलबदल कानून-संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की धाराएं'' तथा ''विधायिकाओं में ए.आई. का उपयोग'' जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।

दलबदल कानून लोकतंत्र की शुचिता की रक्षा के लिये बना है लेकिन, समय के साथ इसमें व्याख्यात्मक पेचिदगियां और राजनीतिक विवेक की जटिलताएं बढ़ी हैं। इस पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श हो, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बना रहे और जनमत का अपमान न हो।

जहां तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रश्न है यह तकनीक अब भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुकी है। इसके माध्यम से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, विधायी शोध, वर्चुअल बैठकों और डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में विधायिकाएं अपने कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बना सकती हैं।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तकनीक मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक मूल्यों के स्थान पर न आ जाए, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ करें।

राज्यपाल ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की शक्ति उसकी बहस, चर्चा और संवाद की संस्कृति में निहित है। यह कॉन्फ्रेंस उसी परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दो दिनों में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं, वे न केवल राज्य विधायिकाओं की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाएंगे, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि यह सम्मेलन ''डिजिटल युग में सुशासन: संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना'' जैसे विषय पर केंद्रित रहा, जो न केवल समय की मांग है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक दिशा भी तय करता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संसाधनों का कुशल प्रबंधन, सेवाओं की पारदर्शिता और नीति-निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। सुशासन अब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कृष्टिकोण बन चुका है, जिसमें नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बदलाव विधायिकाओं को भी तकनीक और पारदर्शिता के साथ अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर राज्य सभा के उप सभापति डॉ. हरिवंश, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व विधान सभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भी अपने विचार रखे।

**शैल समाचार संपादक मण्डल**

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, पूर्ण सहायता का दिया आश्वासन

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के धर्मपुर में लौंगणी पंचायत के आपदा प्रभावित स्याठी गांव का दौरा किया। उन्होंने बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। बादल फटने की घटना से 61 लोग प्रभावित हुए हैं तथा घरों, गौशालाओं और पशुओं को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन मंडी ने प्रभावितों को 1.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, राशन आपूर्ति, तिरपाल और अन्य राहत सामग्री सहित तत्काल सहायता प्रदान की है।

प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है तथा आपदा के इस मुश्किल दौर में व्यक्तिगत रूप से आपका दुख साझा करने आया हूं। उन्होंने प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज तथा गाय, बकरी, भेड़ सहित पशुधन के नुकसान के साथ-साथ नष्ट हुए गौशालाओं के लिए भी बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रभावित परिवारों ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि इस आपदा में पूरा गांव बह गया तथा अब उनके पास तंबू लगाने के लिए भी जमीन नहीं बची है। कई लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। प्रभावितों द्वारा जमीन उपलब्ध करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध होगी तो उन्हें आवंटित की जाएगी। वन भूमि क्षेत्र में यदि जमीन है तो यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडी-कोटली सड़क को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के स्याठी गांव में भूस्खलन से 20 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा 61 लोगों को समय रहते सुरक्षित राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। उन्होंने चट्टानी सतह के खिसकने के कारणों का पता लगाने तथा अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की आठ से दस घटनाएं घटित हुई हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से ऐसी घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के थुनाग, जंजैहली और बगस्याड़ क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। मंडी जिला में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 अन्य लापता हैं। गोहर उपमंडल में पांच, थुनाग में तीन और जोगिंद्रनगर व करसोग में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है तथा प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान की जा रही है।

धर्मपुर के विधायक चंद्र शेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशील नेतृत्व का परिचय देते हुए 24 घंटे के भीतर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों के दर्द को साझा किया है।

# आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर चल रहा सड़कों, बिजली व जलापूर्ति योजनाओं का बहाली कार्य:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मूसलाधार बारिश, बादल फटने व भूस्खलन के कारण राज्य में सबसे अधिक सभी प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से जिला मंडी के थुनाग, जंजैहली में राहत और पुनर्वास के कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की दोनों टीमें जंजैहली और थुनाग उपमंडल के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। इसके अलावा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, निदेशक ऑपरेशन, राज्य विद्युत बोर्ड और मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग बहाली कार्यों की निगरानी के लिए थुनाग में तैनात हैं। इसके अलावा होमगार्ड, पुलिस और स्वयंसेवकों की टीमें भी राहत और बहाली कार्यों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को परस्पर समन्वय के साथ काम करने और विशेष रूप से अति प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति और बिजली बहाली के लिए त्वरित और समयबद्ध कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य भर में लगभग 392 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। लोक निर्माण विभाग युद्धस्तर पर बहाली कार्य में जुटा है, जिसमें 289 जेसीबी और एसकेवेटर, 15 रोबोट, 16 डोजर्स तथा 111 टिप्पर लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सड़क मार्गों की सफाई हो सके। 20 जून से 3 जुलाई के बीच सड़क अधोसंरचना को लगभग 182 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां 189 सड़कों पर यातायात बाधित हैं और लगभग 47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जिला में 84 जेसीबी व एस्केवेटर, एक रोबोट, तीन डोजर तथा 36 टिप्पर लगाए गए हैं ताकि महत्त्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग शीघ्र बहाल किए जा सकें।

जल शक्ति विभाग द्वारा पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं । प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, जल शक्ति विभाग की फील्ड टीमें और इंजीनियर पूरी लगन से कार्य में जुटे हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रहे हैं। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, विभाग ने क्लोरीनेशन के बाद गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली से छोटी योजनाओं को सक्रिय कर दिया है, ताकि प्रभावित गांवों में साफ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, हैंडपंपों और प्राकृतिक जल स्रोतों के माध्यम से भी पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें। साथ ही पानी की गुणवत्ता की निगरानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई हैं।

जिला मंडी में आपदा के कारण चार सब-स्टेशन और 1708 वितरण ट्रांसफार्मर बंद हो गये थे तथा कई किलोमीटर लंबी विद्युत लाइनें पूरी तरह से बह गई थीं। केवल दो दिनों में तीन सब-स्टेशन और 1294 ट्रांसफार्मर को बहाल कर दिया गया है।

सुक्खू ने कहा कि 33 केवी गोहर-थुनाग लाइन को बहाल कर दिया गया है और थुनाग में जरूरी सामग्री की आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाएगी। 33 केवी गोहर-पंडोह लाइन को शीघ्र बहाल किए जाने की उम्मीद है। गोहर विद्युत मंडल की टीम ने 2 जुलाई को पैदल थुनाग पहुंचकर 33 केवी सब-स्टेशन को चालू किया तथा इसके माध्यम से अस्पताल, राहत शिविर, मिनी सचिवालय जैसे महत्त्वपूर्ण सेवाओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जंजैहली क्षेत्र और इसके आसपास बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड युद्धस्तर पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कार्यरत हैं और प्रभवित क्षेत्रों में 60 लोगों की पांच टीमों को तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि थुनाग और आसपास के क्षेत्र में बोर्ड को लगभग 20 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। इस दौरान 33 केवी गोहर-थुनाग-जंजैहली लाइन और गोहर-पंडोह लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अतिरिक्त, थुनाग और आसपास के क्षेत्र से 8 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन को भी नुकसान पहुंचा है और 258 ट्रांसफार्मरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बोर्ड के निदेशक ऑपरेशन, मंडी जोन के मुख्य अभियंता और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडी के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा थुनाग क्षेत्र में इंट्रा सर्किल रोमिंग आईसीआर को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन संचार के लिए आईसेट को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राहत और पुनर्वास कार्यों की निरंतर निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है।

# मुख्यमंत्री ने आरजीएसएसवाई के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में दो साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केन्द्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को देख रहे हैं। इसके दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान कर नीतियां बनाई जा रही हैं। इस दिशा में ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है।

# विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित करेगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इच्छुक युवाओं का व्यापक डेटा संकलित किया जाएगा, जिससे विदेश में नौकरी पाने के दौरान पारदर्शिता बेहतर पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एचपीएसईडीसी को पंजीकृत भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उन्होंने एचपीएसईडीसी को अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप राज्य के युवाओं के कौशल संवर्द्धन के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं और लगभग 5,000 युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में यह संख्या क्षमता से कम है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में विदेशों में काम करने वाले हिमाचलियों ने विदेशों से कुल 2,030 करोड़ रुपये भेजे, जो राष्ट्रीय प्रेषण आंकड़ों का लगभग 0.2 प्रतिशत है। यह राज्य की अपेक्षाकृत छोटी आबादी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में नर्स, वेटर, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता, क्लर्क, ड्राइवर हल्के और भारी ड्यूटी, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर और मैकेनिक जैसे पेशेवरों की भारी मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिमाचल प्रदेश के युवा इन व्यवसायों में प्रशिक्षित हैं और एचपीएसईडीसी प्रदेश के युवाओं को विदेशों में प्लेसमेंट के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल पंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग को हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए केरल और तेलंगाना के विदेशी रोजगार मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार की दर सबसे अधिक केरल राज्य में है, जहां प्रति 1,000 में से 57.94 व्यक्ति विदेश में काम कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह संख्या प्रति 1,000 में से केवल 5.36 है। उन्होंने विभाग को हिमाचली एनआरआई का डेटा बेस तैयार करने के भी निर्देश दिए।

# मुख्यमंत्री ने हमीरपुर बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में निर्माणाधीन बस अड्डे का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे का कार्य अगले वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण गत 20 वर्षों से इस बस अड्डे का निर्माण कार्य लंबित था। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस बस अडडे का निर्माण कार्य तीव्र गति से करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस अड्डे के धरातल तल को पार्किंग सुविधा के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर को शीघ्र ही लोगों को समर्पित किया जाएगा जिससे क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद के आदेश दिए गए हैं।

# सोलन के बसाल में 24 करोड़ रुपये से निर्मित होंगे दो ट्विन टावर्ज: राजेश धर्माणी

**शिमला/शैल।** नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में सतत और समावेशी शहरी विकास के दृष्टिगत नवाचार अपनाकर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस क्रम में जिला सोलन के बसाल में हाउसिंग कॉलोनी में दो ट्विन टावर्ज के निर्माण के लिए 24 करोड़ 49 लाख 41 हजार 700 रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन ट्विन टावर में तीन बीएचके के 24 फ्लैट निर्मित किए जाएंगे जिनमें फ्लैट मालिकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी रहेगी।

उन्होंने कहा कि हिमुडा प्रदेश में लोगों को किफायती और सुविधाजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। प्रदेश में बेहतर बुनियादी अधोसंरचना के साथ निर्माण कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

# राशन वितरण में फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल:गोकुल बुटेल

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

बुटेल ने बताया कि अब तक लाभार्थियों का सत्यापन ओटीपी या बायोमीट्रिक के माध्यम से किया जाता था। इन प्रक्रियाओं में एसएमएस डिलीवरी की विफलता और यूआईडीएआई में बायोमीट्रिक मिलान में समस्याएं आती थीं, जिससे लाभार्थियों को असुविधा होने के साथ-साथ सेवा वितरण में भी विलंब भी हो रहा था। यह राज्य के उचित मूल्य की दुकान एफपीएस डीलरों से प्राप्त सबसे सामान्य शिकायतों में से एक थी।

उन्होंने बताया कि नई फेस अथेंटिकेशन प्रणाली इन चुनौतियों को दूर करते हुए लाभार्थियों का सत्यापन एफपीएस डीलर के स्मार्टफोन में लगे कैमरे से चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से करती है। यह प्रक्रिया एक सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होती है, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी या बायोमीट्रिक हार्डवेयर पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस पहल के कार्यान्वयन से सत्यापन की सफलता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और प्रक्रिया की समयबद्धता में भी भारी कमी आई है। अब लाभार्थियों को उनके हक का राशन समय पर मिल रहा है।

भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं।

.....महात्मा गांधी

## सम्पादकीय

# क्या यह त्रासदी चिंता और चिंतन का विषय नही?

हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर प्राकृतिक आपदा ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में भारी बरसात व बादल फटने की घटनाओं से अब तक 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका। पिछले दिनों मंडी जिला में 123 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां बहुत तबाही हुई है। शिमला जिला में 105 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। हाल ही में 14 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई है। इस भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में बहुत सी सड़कें अवरूद्ध हुई है जलापूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है तथा बिजली के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति हुई है। जंगल कटान और अवैध खनन के कारण आज इस त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में जमा हुई लकड़ी से संबंधित मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गयी है इस तरह के फैसले लेने होंगे। प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है जोकि एनएचएआई, मोर्थ और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनमें जहां कहीं भी नियमों की अनदेखी हो रही है उस पर सख्त कारवाई होनी चाहिये। अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ो की कटींग पर भी रोक लगानी होगी। वनों के अवैध कटान के मामलों में दोषियों के खिलाफ कारवाई करनी होगी नही तो हर बरसात में ऐसा ही भोगना पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ इस आपदा को कुदरत का कहर मानने की बजाये इसे मानव निर्मित त्रासदी की संज्ञा दे रहे हैं और यही चिंता और चिंतन का सबसे बड़ा विषय है।

हिमाचल का अधिकांश हिस्सा गहन पहाडी क्षेत्र है। गलेशियरो का प्रदेश है। हर पहाड़ पानी का स्त्रोत है । नदी, नालों का प्रदेश है। इसी पानी की बहुलता और पहाड़ों के नैर्सगिक सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे बिजली ऊर्जा राज्य के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया। हर छोटे-बड़े नदी नाले का अध्ययन हुआ और बिजली उत्पादन की क्षमताओं के आंकड़े आते चले गये। चंबा से लेकर सिरमौर तक 504 छोटी बड़ी विद्युत परियोजना चिन्हित हो गई। यह प्रचारित हो गया कि हिमाचल इस बिजली के सहारे ही आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा। विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल सरकार केंद्र सरकार और प्राइवेट सैक्टर सब कूद पड़े। इन परियोजनाओं के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए और दरियाओं का वास्तविक प्रभाव की बदल दिया गया। जबकि परियोजना निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह जितने पेड़ काटेंगे उसके 10 गुना उन्हें लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि वास्तव में कटे पेड़ों की जगह कितने नए पेड़ लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं से जो पर्यावरणीय बदलाव पैदा हुए हैं आज हो रहे नुकसान का शायद पहला मूल कारण यह है।

विद्युत के साथ ही प्रदेश को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना है। शहरों से गांवों की ओर होमस्टे की अवधारणा को कार्यरूप दिया जा रहा है। शिमला सहित सारे पर्यटक स्थलों को जिस तरह से कंकरिट के जंगल में बदल दिया गया है उसको लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक प्रदेश सरकारों को फटकार लगा चुका है। शिमला में एक समय रिटैन्शन पॉलिसीयों पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाये थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया । अगर इन आपदाओं से आज कोई सबक नहीं लिया जाता है तो भविष्य में और भी बड़े संकटों के लिए तैयार रहना होगा ।

# परिवर्तन को समर्थ बनाना : महिला एवं बाल विकास में तकनीकी परिवर्तन का एक दशक

## सशक्तिकरण की शुरुआत पहुंच-अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होनी चाहिए

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

सशक्तिकरण की शुरुआत पहुंच-अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होती है। बीते दशक में, अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त भारत का निर्माण करने पर केंद्रित मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से इस पहुंच को नए सिरे से परिभाषित किया गया है और सभी के लिए सुलभ बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस परिवर्तन में सबसे अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047के विजन से निर्देशित, मंत्रालय ने लाभ को अंतिम छोर तक त्वरित, पारदर्शी और कुशल तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी कोव्यवस्थित रूप से एकीकृत किया है।

हम अक्सर कहते हैं : सशक्त महिलाएं, सशक्त भारत और सशक्तिकरण की शुरुआत पहुंच- अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होनी चाहिए । आज, यह पहुंच तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है।

जो कभी आकांक्षापूर्ण था, वह अब क्रियाशील बन चुका है।ऐसा सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रियल-टाइम डेटा सिस्टम और उत्तरदायी शासन पर ज़ोर दिए जाने की बदौलत संभव हुआ है।

मंत्रालय ने देख रेख, संरक्षण और सशक्तीकरण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करते हुए-पोषण, शिक्षा, कानूनी सुरक्षा और आवश्यक अधिकारों तक पहुंच को मजबूत किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं और बच्चे न केवल अधिक स्वस्थ, अधिक सुरक्षित जीवन जी सकें, बल्कि वे आत्मविश्वासी नेतृत्वकर्ता और अमृत काल के परिवर्तनकर्ता के रूप में भी उभर सकें।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सटीक रूप से कहा है, मैं प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के साधन के रूप में तथा आशा और अवसर के बीच की दूरी को पाटने वाले उपकरण के रूप में देखता हूं। इस लोकाचार ने मैनुअल प्रक्रियाओं से लेकर रियल-टाइम डैशबोर्ड तक, असंबद्ध योजनाओं से लेकर एकीकृत प्लेटफार्मों तक हमारे परिवर्तन का मार्गदर्शन किया है।

इस परिवर्तन की आधारशिला सक्षम आंगनवाड़ी पहल है। भारत भर में 2 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए निरुपित यह कार्यक्रम बाल्यावस्था देखरेख और विकास की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण, स्वास्थ्य सेवा और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा सेवाओं की ज्यादा प्रभावी प्रदायगी संभव बनाते हुए इन केंद्रों कोस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइस और नए-नए लर्निंग टूल्स के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।

देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पोषण ट्रैकर के साथ एकीकृत करने से रियल-टाइम डेटा एंट्री, कार्य निष्पादन की निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो पाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और व्यापक प्रशिक्षण से लैस करके, यह पहल अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करती है। यह 2014 से पहले मौजूद मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग और डेटा ब्लाइंड स्पॉट से एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

एक दशक पहले, आईसीडीएस प्रणाली असंबद्ध डेटा, विलंबित प्रतिक्रियाओं और रियल-टाइम ट्रैकिंग की कमी से दबी हुई थी। पोषण ट्रैकर ने-पोषण सेवा प्रदायगी में सटीकता, दक्षता और जवाबदेही की शुरुआत कर इस परिदृश्य को बदल दिया है ।

10.14 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी। अब इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं- जिनमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, छह साल से कम उम्र के बच्चे और किशोरियां शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म विकास की निगरानी और पूरक पोषण प्रदायगी पर रियल-टाइम अपडेट को सक्षम बनाते हुए समय पर हस्तक्षेप और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित करता है। डिजिटल रूप से सशक्त सामुदायिक केंद्रों के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों कीनए सिरे से परिकल्पना कर,शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए- पोषण ट्रैकर महत्वपूर्ण रूप से स्वस्थ भारत, सुपोषित भारत के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ा रहा है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित यह मंच 'पोषण भी पढाई भी' का भी समर्थन करता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करते हुए विकसित भारत के अमृत काल में समग्र देखभाल को बढ़ावा दे रहा है।

पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) में पारदर्शिता को और मजबूत करने तथा लीकेज कम करने के लिए एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है। इस डिलिवरी तंत्र को सुरक्षित, सटीक और सम्मानजनक बनाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि पोषण सहायता केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले।

प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यह मंत्रालय पोषण से बढ़कर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित कर रहा है। शी-बॉक्स पोर्टल हर महिला को, चाहे वह किसी भी रोजगार की स्थिति में हो या संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो, पॉश अधिनियम के तहत उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए सिंगल-विंडो एक्सेस प्रदान करता है-जिससे ऑनलाइन निवारण और ट्रैकिंग संभव हो पाती है। इस बीच, मिशन शक्ति डैशबोर्ड एंड मोबाइल ऐप संकट से घिरी महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करता है, उन्हें निकटतम वन स्टॉप सेंटर से जोड़ता है -जो अब लगभग हर जिले में चालू है। ये कदम इस बात का उदाहरण हैं कि तकनीक का उपयोग न केवल दक्षता के लिए, बल्कि न्याय, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भी किया जा रहा है।

एक दशक पहले, मातृत्व लाभ की निगरानी करना मुश्किल था और इसमें देरी होती थी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई की शुरूआत की है - जो मातृ कल्याण की दिशा मे बहुत बड़ा बदलाव है। पीएमएमवीवाई नियम, 2022 के तहत, गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि मिलती है । मिशन शक्ति के तहत, अगर दूसरा बच्चा लड़की है, तो - बेटियों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देते हुए लाभ की राशि 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है। कागज रहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से वितरित,शुरुआत से अब तक 4 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों तक 1,9000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच चुकी है।

पीएमएमवीवाई-आधार-आधारित प्रमाणीकरण, मोबाइल-आधारित पंजीकरण, आंगनवाड़ी@आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सहायता और रियल-टाइम डैशबोर्ड का लाभ उठाते हुए एक पूर्णत: डिजिटल कार्यक्रम है। एक समर्पित शिकायत निवारण मॉड्यूल तथा पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला नागरिकों से संबंधित पोर्टल है-जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

ये लक्षित प्रयास ठोस नतीजे दे रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एमओएचएफडब्ल्यू की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली एच एम आई एस की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) **918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24)** हो गया है, जिसमें 12 अंकों का शुद्ध सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। **मातृ मृत्यु दर 130 प्रति 1000 जन्म (2014-16) से घटकर 97 प्रति 1000 जन्म (2018-20)** हो गई है-जो हमारी सरकार के पिछले एक दशक के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है।

प्रत्येक बच्चा पोषित, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण का हकदार है। हाल के वर्षो में, डिजिटल परिवर्तन ने बाल संरक्षण और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। **किशोर न्याय अधिनियम** के तहत, मंत्रालय ने के यरिंगसपोर्टल बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से गोद लेने के इकोसिस्टम को मजबूत किया है। यह डिजिटल इंटरफ़ेस एक अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल गोद लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

डिजिटलीकरण ने बाल देखभाल संस्थानों,पालन-पोषण केंद्रों और जेजे अधिनियम के तहत वैधानिक सहायता संरचनाओं की निगरानी में भी सुधार किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म बाल अधिकारों के उल्लंघन पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहे हैं। इस बीच, मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड विभिन्न बाल कल्याण हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय को मजबूत करता है।

यह नया भारत है - जहाँ शासन प्रौद्योगिकी से मिलता है, और जहाँ नीति उद्देश्य से मिलती है। पिछले दशक में, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने न केवल डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है-बल्कि इसका समर्थन भी किया है।

जैसे-जैसे हम अमृत कालमें आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रालय प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे का राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनना सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व करना जारी रखेगा। प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और लक्षित कार्रवाई के माध्यम से, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहाँ सशक्तिकरण महज नारा भर नहीं है-बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए वास्तविकता है।

*लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।*

# पर्यावरण के रचनात्मक प्रशासन के जरिए सतत हरित बदलाव

–भूपेंद्र यादव–
केन्द्रीय पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

पर्यावरण कुजनेट्स वक्र (एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व) से हासिल पर्यावरण के प्रशासन से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि देश पहले विकास करते हैं और बाद में सफाई में जुटते हैं। यह अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि अब विकसित हो चुके उन देशों के अनुभवों से प्रेरित है, जिन्होंने विकास की प्रक्रिया में संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु देश और विदेश में प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन किया। लेकिन ऐसी सुविधा भारत जैसे देशों को नसीब नहीं है, जिन्हें अपनी विशाल आबादी की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभी भी तेज गति से विकास करने की जरूरत है।

जब 2014 में एनडीए सत्ता में आई, तो चुनौती हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल सिद्धांतों में **–''सुधार, प्रदर्शन और बदलाव''–** पर आधारित विकास एवं प्रगति को गति देने की थी। इन सिद्धांतों में जरूरत के हिसाब से पर्यावरण की सुरक्षा के सख्त उपायों से समझौता किए बिना 'व्यवसाय करने में आसानी' की सुविधा प्रदान करते हुए तेजी गति से विकास करना शामिल था। आज 2025 में, हम न सिर्फ इस चुनौती से निपट पाने में सफल रहे हैं बल्कि हमने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे सारी दुनिया ने माना है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। इस प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदला जाये जो इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो। वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत हमारी पहली बड़ी पहल थी। यह पहल स्वच्छता से आगे बढ़कर कचरे के प्रबंधन व पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने तक जा पहुंची। इस मिशन ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को सामाजिक विकास के साथ जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस मिशन को सभी नागरिकों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और एक स्वच्छ एवं संसाधन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक कुशल भारत की चाहत को आगे बढ़ाया गया था। विभिन्न शहरों में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी सुविधा प्रदान करने के तुरंत बाद राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल में भी कड़े पर्यावरण अनुपालन मानकों को शामिल किया गया। इससे यह साबित हुआ कि हम इकोलॉजी की स्थिरता को बनाए रखते हुए मैन्यूफैक्चरिंग को अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर और तेज गति से बढ़ावा दे सकते हैं। ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा पर आधारित अधिक संख्या में उद्योगों को शामिल करने के उद्देश्य से 2015 में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का विस्तार किया गया।

इससे ऊर्जा संबंधी दक्षता के लिए एक बाजार–आधारित तंत्र का निर्माण हुआ। कचरे के कारगर प्रबंधन, संसाधन संबंधी दक्षता में बढ़ोतरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से कचरे के प्रबंधन के सभी प्रमुख नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का बुनियादी सिद्धांत बाजार आधारित तंत्र और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत पर आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से जुड़े ढांचे पर निर्भरता में निहित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई–कचरा प्रबंधन नियम तथा टायर, बैटरी एवं प्रयुक्त तेल अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए थे। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जिसके तहत विभिन्न सामग्रियों के लगभग 4,000 पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है। इस कदम से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर पोर्टल चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल 61,055 उत्पादकों ने प्लास्टिक पैकेजिंग, ई–कचरा, बेकार टायर, बैटरी के कचरे और प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में काम करने हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अपशिष्ट नियम, 2022 के प्रकाशन और ईपीआर पोर्टल की शुरूआत के बाद, शोधित अपशिष्ट की मात्र वित्तीय वर्ष 2024–25 में इन नियमों के प्रकाशन से पहले 3.6 एमएमटी प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 127.48 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है। यह सभी हितधारकों के सहयोग एवं समर्थन से संभव हुआ है।

प्रक्रियागत देरी में कमी लाने और एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 2018 में 'परिवेश' प्रो–एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरएक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरनमेंटल सिंगल–विंडो हब नाम के एक ऑनलाइन आईटी टूल का शुभारंभ किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन को साकार करते हुए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यवसाय जगत और पर्यावरण नियामकों के बीच के संवाद में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है।

'परिवेश' ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बोझिल एवं कागज–आधारित प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित एवं मजबूत डिजिटल अनुभव में बदल दिया है। इस दृष्टिकोण ने जहां पर्यावरण से जुड़े सख्त मूल्यांकन को बनाए रखा है, वहीं इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी ला दी है और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

वर्ष 2019 में शहरों पर केन्द्रित कार्य योजनाओं से लैस 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) के आधिकारिक शुभारंभ ने हमें नीति निर्माता एवं नियामक से बदलकर अमल करने वाला बना दिया है। एनसीएपी का लक्ष्य 2025–26 तक पीएम 10 सांद्रता में 40 प्रतिशत की कमी लाना या आधार वर्ष 2017–18 की तुलना में 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के राष्ट्रीय मानक को हासिल करना है। एनसीएपी के साथ–साथ सीपीसीबी ने एनसीएपी के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता के रुझान की बारीकी से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वायु की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हुई है। वर्ष 2021 में, गैर–प्राप्ति वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के नियमन हेतु पोर्टल पीआरएएनए को कागज रहित परियोजना प्रबंधन के एकल बिंदु वाले वेब–आधारित उपकरण के रूप में शुरू किया गया। इससे स्वच्छ वायु से जुड़े उपायों के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नजर रखना संभव हो सकेगा।

1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक शीट पर प्रतिबंध ने जहां पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया, वहीं उसी वर्ष शुरू किए गए 'जल जीवन मिशन' ने पानी की सुलभता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा।

एक व्यापक 'भारत शीतलन कार्य योजना' विकसित करके भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस कार्य योजना में विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण समावेश है तथा इसमें ऐसे कार्यों की सूची दी गई है, जो शीतलन से जुड़ी मांग को कम करने में सहायक हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन की जरूरत होती है तथा यह आर्थिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन, कोल्ड–चेन, प्रशीतन, परिवहन और उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जरूरत पड़ती है।

भारत ने हाइड्रोक्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उत्सर्जन में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने हेतु 27 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का अनुमोदन किया। इसके तहत 2032 से आगे चार चरणों में चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है और 2032, 2037, 2042 एवं 2047 में उत्सर्जन में क्रमश: 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 85 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

वर्ष 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना की। इससे उत्सर्जन में कमी से संबंधित बाजार आधारित तंत्र का निर्माण हुआ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत 2023 में हमारी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का संचालन देश के पहले व्यापक कार्बन बाजार के निर्माण की राह में एक अहम पड़ाव है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सीओपी26 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 'मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मानव व्यवहार को प्रेरित करके टिकाऊ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने वाला एक और अनुकरणीय कदम है।

कार्बन क्रेडिट के अलावा, 'ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम' के रूप में एक सकारात्मक उपाय की शुरुआत 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में सीओपी28 के दौरान की गई ताकि पर्यावरण से संबंधित सकारात्मक कार्यों को पुरस्कृत किया जा सके और स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रबंधन को प्रेरित करने वाले प्रोत्साहनों का सृजन किया जा सके।

वर्ष 2024 में देश भर में भारत स्टेज VI (बीएस–VI) उत्सर्जन मानदंडों का पूर्ण कार्यान्वयन और टिकाऊ वित्त हेतु हमारे हरित कर प्रणाली ग्रीन टैक्सोनॉमी के ढांचे का विकास ऐसे कदम हैं जो स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये कदम इस बात को भी दर्शाते हैं कि पर्यावरण से जुड़ा प्रशासन कैसे तकनीकी उन्नति और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। पर्यावरण के अनुकूल और गुणवत्ता वाले टिकाऊ उत्पादों के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रलय ने ई(पी) अधिनियम, 1986 के तहत इकोमार्क नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। इसमें उत्पादन और उपभोग की टिकाऊ पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादों की 80 उप–श्रेणियों के साथ 17 व्यापक श्रेणियां शामिल की गई हैं और सीपीसीबी को प्रमुख प्रशासनिक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष 2018 में 'परिवेश' के शुभारंभ से लेकर 2024 में 'परिवेश 2.0' तक का विकास, पर्यावरण संबंधी प्रबंधन एवं निगरानी की प्रक्रिया में निरंतर तकनीकी व गुणात्मक सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 'परिवेश 2.0' में जीआईएस से लैस एक आधुनिक निर्णय समर्थन प्रणाली और एक बेहतर पर्यावरणीय मूल्यांकन सुविधाओं का समावेश है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में पर्यावरण संबंधी मंजूरी को समन्वित करने से व्यवसाय संबंधी अनुमोदन का एक 'वन–स्टॉप' डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। इससे व्यवसाय करने में आसानी से जुड़ी विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत का स्थान की नाटकीय रूप से बेहतर हुआ। भारत इस रैंकिंग में 2014 में 142वें स्थान से उछलकर 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। वर्ष 2014–2020 के बीच, हमने 2,115 आवेदनों में से लगभग 2,053 परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान की जिससे आवेदनों को निपटाने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

कचरे के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के उद्देश्य से, उद्योगों को वर्गीकृत करने की एक नई पद्धति शुरू की गई है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत विभिन्न गतिविधियों को लाल, नारंगी, हरे, सफेद और नीले रंग की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

नीले रंग की नई श्रेणी वाले उद्योग सीवेज शोधन संयंत्र, खाद बनाने वाली इकाई, बायोगैस संयंत्र और सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति से जुड़ी सुविधा जैसे पर्यावरण के अनुकूल सकारात्मक उपायों से लैस होते हैं।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ा हमारा प्रशासकीय ढांचा उन्नत एआई क्षमताओं, उन्नत सार्वजनिक भागीदारी तंत्र और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से लैस होकर विकसित होता जा रहा है। उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली और ईएसजी रिपोर्टिंग की ठोस व्यवस्थाओं समेत 2025 में हुए हालिया विकास, अत्याधुनिक बने रहने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाते हैं। लालफीताशाही से लेकर हरित रचनात्मकता तक की दशक भर की यह यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि एक दूरदर्शी नेतृत्व बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करता है।

अब जबकि हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, एक दशक से अधिक समय में लागू किया गया पर्यावरण से जुड़ा प्रशासकीय ढांचा टिकाऊ विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

# पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ईएलआई योजना के तहत दो किस्तों में 15 हजार रुपये तक देगी केंद्र सरकार

**शिमला।** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त– राकेश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि भारत सरकार ने सभी व्याप्त संस्थानों के लिए यह योजना लागू की है परन्तु विनिर्माण क्षेत्र के संस्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को मंजूरी दे दी है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त– राकेश कुमार ने ईएलआई योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ईएलआई योजना का उद्देश्य देश में 3. 5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के भाग–ए के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है। भाग–ए से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।

ईएलआई योजना के भाग–बी में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे।

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए या पांच अतिरिक्त कर्मचारी 50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

'10,000 रुपये तक के ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों को आनुपातिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ लोगों के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे ई.एल.आई. योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। क्षेत्रीय आयुक्त ने आहवान किया कि ई. एल.आई. योजना का लाभ उठाने के लिए सभी ई.पी.एफ. सदस्यों को अपना यू.ए.एन. सक्रिय करना होगा। ई.पी.एफ. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे सभी ई.पी.एफ. सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अपना यू.एन.ए.एन. की के.वाई.सी. भी अपडेट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव शर्मा, सहायक निदेशक पीआईबी और ज्योतिन्द्र आजाद, सहायक भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को ग्रीन हाइड्रोजन बसों की संभावना तलाशने के निर्देश दिए

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को हिमाचल के

चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनजर राज्य के लोगों के लिये परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2026 तक 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक-बसें संचालित की जाएंगी, जबकि 30 टाइप-2 इलेक्ट्रिक-बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने एचआरटीसी अधिकारियों को निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च, 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने रियायती पास के लिए आवेदन करने के लिए एकल बस पास प्रणाली और वास्तविक समय बस निगरानी प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्य और प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा एचआरटीसी मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला शिमला के ठियोग में एचआरटीसी कार्यशाला स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार निगम को एक व्यवहार्य संस्थान बनाने के लिए हर तरह से सहयोग कर रही है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बैठक के दौरान बहुमूल्य सुझाव दिए और निगम के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की।

# शिक्षा मंत्री ने गुणत्तापूर्ण शिक्षा और खेल विकास पर बल दिया

**शिमला/शैल।** शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मामलों और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) में प्रदेश की बड़ी छलांग को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में प्रदेश 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा है। यह राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य कर रहे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना पहले ही शुरू की है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष से पहली बार कॉलेज शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जायेगा।

रोहित ठाकुर ने बताया कि 12 नए डे-बोर्डिंग स्कूलों की आधारशिलाएं रखी गई हैं और इन्हें जल्दी ही आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 56 अन्य स्कूलों को डे-बोर्डिंग स्कूलों में स्तरोन्नत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अटल आदर्श विद्यालयों का स्वयं निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने 187 दिव्यांग जेबीटी और 194 शास्त्री शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ड्राइंग मास्टर्स की भर्ती भी समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल की आवश्यकता और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की तैनाती की जाये तथा अनावश्यक डेपुटेशन रद्द कर केवल अति-आवश्यक होने पर ही डेपुटेशन दी जाये।

उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और शून्य परिणाम वाले स्कूलों पर कड़ी कारवाई की जाये और उन शिक्षकों की पहचान करने को कहा जो बच्चों को गुणत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मेधावी छात्रों को समय पर टैबलेट वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक, प्रिंसिपल, प्रवक्ता (पीजीटी) और अन्य शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

रोहित ठाकुर ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में नए कौशल आधारित व व्यावसायिक विषय आरम्भ किए जाएंगे। इसके अलावा, उन कॉलेजों में मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषय भी शुरू किए जाएंगे जहां अभी तक यह विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार खेल को बढ़ावा देने और खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्य में अंडर-19 राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी और हैंडबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। खिलाड़ियों के लिए डाइट और यात्रा भत्ते बढ़ाने के साथ-साथ खिलाड़ियों को हॉस्टल सुविधा और यात्रा में एसी ट्रेन व हवाई यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।

मंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा खर्च न की गई धनराशि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसका उपयोग शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाये। उन्होंने कहा कि विशेषकर पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत मिली राशि को 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए खर्च किया जाए।

उन्होंने अनुपूरक पुस्तकों में प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और लोक नायकों को शामिल करने के लिए एससीईआरटी और एसआरजी से पाठयक्रम सुधार के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

# आपदा प्रभावित मंडी ज़िले में भेजी गई 1738 राशन किट

**शिमला/शैल।** मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं सहित राशन व खाद्य सामग्री की आपूर्ति का कार्य लगातार जारी है। जिला में अभी तक 1738 राशन किट का वितरण किया जा चुका है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि सड़क सम्पर्क सीमित होने के कारण हवाई मार्ग के अलावा पैदल व खच्चरों के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। आपदा से बुरी तरह प्रभावित थुनाग के लिए 197 राशन किट भेजी गई हैं। इनमें ग्राम पंचायत थुनाग के लिए 157, झुंडी के लिए 46, सरन के लिए 16, पखरैर के लिए 34, लेहथाच के लिए 10 राशन किट शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि जंजैहली के लिए 269 राशन किट उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय तक पहुंचा दी गई हैं। यह राशन सामग्री जीभी से आये पोर्टर व स्थानीय लोगों को सहयोग से रेशन से यहां तक पहुंचाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, बगस्याड में एक हजार राशन किट पहुंचाई जा चुकी हैं। इनमें से 180 राशन किट बगस्याड के राहत शिविर के लिए, खनुगी के लिए 60, फनैर के लिए 15 राशन किट भेजी गई हैं। सुराह के 70 राशन किट खच्चरों व पोर्टर के माध्यम से भेजी गई हैं। शंकरदेहरा के लिए 13 राशन किट भेजी गई हैं।

उपायुक्त ने बताया कि जिला के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में धर्मपुर के लिए 50 राशन किट, गोहर के बाड़ा के लिए 50, स्यांज के लिए 50 तथा जोगिंदर नगर के चौंतड़ा के लिए 09 राशन किट भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडर, डीजल, तिरपाल इत्यादि अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस राहत सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में सहयोग के लिए सभी कर्मचारियों, स्वयंसेवियों व स्थानीय लोगों का आभारी है। फौरी राहत के रूप में मंडी जिले के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 19.35 लाख रुपये जारी किए गए हैं। थुनाग के लिए 6.50 लाख रुपये, गोहर के लिए 7 लाख रुपये, धर्मपुर के लिए 3 लाख रुपये, करसोग के लिए 2.50 लाख रुपये, बाली चौकी के लिए 20 हज़ार, सुंदरनगर के लिए 10 हज़ार रुपये और सरकाघाट के लिए 5 हज़ार रुपये की धनराशि जारी की गई है।

# भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जल शक्ति विभाग की 3,698 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त

**शिमला/शैल।** उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जल शक्ति विभाग की 3,698 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें 2,786 जलापूर्ति, 733 सिंचाई और 41 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक लगभग 240 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया गया है।

मुकेश अग्निहोत्री ने हालात की गंभीरता को देखते हुए जल शक्ति विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा विभाग ने युद्धस्तर पर बहाली का कार्य आरंभ कर दिया है। उन्होंने विभाग को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल और सीवरेज सेवाओं को बहाल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि अब तक 1,591 जलापूर्ति परियोजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी दिन-रात कार्य में जुटे हुए हैं ताकि शेष परियोजनाओं की बहाली भी शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के इस मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ी है और जल शक्ति विभाग हर संभव संसाधन का उपयोग कर परियोजनाओं की बहाली में जुटा है।

# परम पावन दलाई लामा के कारण से धर्मशाला को मिली वैश्विक पहचान: उप-मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** तिब्बती समुदाय के आध्यात्मिक गुरू परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के अवसर पर छोटा शिमला तिब्बतन स्कूल में भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उप-मुख्यमंत्री मुकेश

अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप-मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को विश्व शांति, करुणा, एकता और मानवता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा की मिसाल है और वह न केवल तिब्बती समुदाय के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की भूमि धर्मशाला में उनका निवास हम सभी के लिए गर्व की बात है। धर्मशाला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का श्रेय भी परम पावन दलाई लामा को ही जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को तिब्बती संस् ति और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत और हिमाचल प्रदेश सरकार ने तिब्बती समुदाय के साथ सदैव ही स्नेह व भाईचारे का व्यवहार किया है। हम तिब्बती समुदाय के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं तथा तिब्बती समुदाय को यहां अच्छा वातावरण मिला है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तिब्बती समुदाय के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर अनेक अहम कदम उठाए हैं और इसमें पूर्व की कांग्रेस सरकारों का अहम योगदान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बौद्ध धर्म एवं परम पावन दलाई लामा के प्रति गहरी आस्था थी। उन्होंने कहा कि तिब्बती समुदाय को वोट देने का अधिकार भी दिया गया है, जो भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल है।

उप-मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में होने वाले मेलों व उत्सवों में तिब्बती कलाकारों को अपनी संस्कृति के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को तिब्बती सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तिब्बती पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को सहेजने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर भारत-तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रो. वी एस नेगी ने तिब्बती संस्कृति और इतिहास पर प्रकाश डाला।

# लोक निर्माण मंत्री ने उच्च मार्गों के निर्माण से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की

**शिमला/शैल।** लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के शिमला स्थित क्षेत्रीय अधिकारी ढलान संरक्षण ऑडिट करवाएंगे, जिसमें आईआईटी को अधिमान दिया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि 30 जून को शिमला के भट्टाकुफर में जो पांच मंजिला भवन ध्वस्त हो गया था, प्राधिकरण 8 जून, 2020 को गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप भवन मालिकों को मुआवजा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह फैसला भी किया गया कि प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, शिमला रियायत प्रदान करने वाला व्यक्ति द्वारा स्थानीय लोगों से सम्पर्क करने के लिए रखे गए व्यक्तियों की सूची उपायुक्त शिमला और उपमंडलाधिकारी, शिमला ग्रामीण को उपलब्ध करवाएगा। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा। विशेष सचिव, लोक निर्माण, प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी , उपमण्डलाधिकारी, शिमला ग्रामीण , प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, टीम लीडर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर और गावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के महा प्रबन्धक बैठक में उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से बात कर नुकसान के बारे में जानकारी

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी वर्षा से मण्डी जिले के सराज तथा धर्मपुर क्षेत्र में लोगों के घरों एवं भूमि को व्यापक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, अगर वे किराये के मकान में रहना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार 5000 रूपये प्रति माह मकान किराया देगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित एसडीएम को प्रभावितों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश से आयी इस आपदा में अभी तक 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 110 व्यक्ति घायल हुए हैं और 37 अभी तक भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही एक बार फिर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बातचीत कर प्रदेश में हुए व्यापक नुकसान के बारे में उन्हें अवगत करवाया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है तथा केंद्रीय टीम भी नुकसान का आकलन करने हिमाचल प्रदेश आ रही है। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून सीजन में ही अभी तक मण्डी जिले में ही 14 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो चिंता का विषय है। बादल फटने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बारे में भी केन्द्रीय गृहमंत्री से भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बरसात व बादल फटने की घटनाओं से अब तक 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में सड़कों, बिजली अधोसंरचना और पेयजल आपूर्ति योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अपने-अपने विभागों की समीक्षा बैठक लेकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए राहत कार्यों में मण्डी जिले में 402 लोगों को बचाया गया है। वानिकी एवं बागवानी कॉलेज, थुनाग में फंसे 92 छात्रों और अध्यापकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। थुनाग के कई गांवों में एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं जो राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटीं हैं।

वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित मण्डी जिला में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है तथा राज्य सरकार प्रभावितों की पूरी मदद कर रही है। सभी विभागों के उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी मशीनरी मण्डी जिला में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें विषम परिस्थितियों के बावजूद लगातार मोर्चे पर डटी हैं। अब तक थुनाग में 65 पीड़ितों को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर में आपदा प्रभावितों के लिए राहत एवं खाद्य सामग्री का वितरण और आवश्यक सेवाओं को युद्ध स्तर पर बहाल करने का कार्य जारी है।

# गोकुल बुटेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हस्ताक्षरित तस्वीर मुख्यमंत्री को भेंट की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, डिजिटल टैक्नोलॉजी एण्ड गवर्नेंस गोकुल बुटेल नें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक दुर्लभ हस्ताक्षरित तस्वीर भेंट की। यह ऐतिहासिक तस्वीर गोकुल बुटेल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे सूर्य बोस ने हाल ही में जर्मनी के हैम्बर्ग की यात्रा के दौरान भेंट की थी।

गोकुल बुटेल ने हाल ही में हैम्बर्ग इंडिया वीक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। इस अंतराष्ट्रीय मंच ने भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूती प्रदान करने का व्यापक मंच प्रदान किया। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हैम्बर्ग के विशेष संबंध पर प्रकाश डाला गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 'फ्री इंडिया सेंटर' की स्थापना और 'इंडियन लीजन' का गठन किया था। इस अवधि के दौरान बोस ने जर्मन संगीतकार विल्हेम हेलबर्ग को 'जन गण मन' के पहले ऑर्केस्ट्रा और सैन्य बैंड संस्करण की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया गया था और जिसे हैम्बर्ग में रचा और रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रस्तुति को आजाद हिंद आंदोलन के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और इसे इंडियन लीजन के आधिकारिक कार्यक्रमों और सैन्य परेडों में बजाया गया और बाद में इसे भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।

हैम्बर्ग को वह शहर होने का गौरव प्राप्त है जहां भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार संगीतबद्ध और प्रस्तुत किया गया, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक गहन सांस्कृतिक मील पत्थर है।

# मुख्यमंत्री ने 24 स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्वो बसों को झण्डी दिखाकर रवाना किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन के क्यारीघाट से 24 स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्वो बसों को हरी झण्डी दिखाने के उपरांत एक जनसभा को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम को और बेहतर बनाने के लिए गत दो वर्षों में प्रति वर्ष एक-एक हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है ताकि लोगों को सुविधाजनक एवं आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 500 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल बसें और लगभग 30 वोल्वो बसें क्रय की गई हैं। भविष्य में भी यातायात सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए 100 टैंपो ट्रेवलर खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को हर माह 60 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में रेलवे तथा वायु परिवहन सुविधाएं अधिक न होने के कारण प्रदेश को यातायात के लिए मुख्यत: सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें लोगों की आवाजाही का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को और बेहतर बनाने के यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में हाईड्रोजन चलित बसों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा से परिपूर्ण हिमाचल न केवल देश के लिए आदर्श स्थापित करेगा बल्कि वैकल्पिक आय स्त्रोतों के साथ हिमाचल की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से प्रदेश में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जिस पर 110 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे जहां हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य बना रहेगा वहीं ग्रीन हिमाचल का सपना भी साकार होगा।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। निगम की यह बसें हिमाचल प्रदेश के लोगों की जीवन रेखाएं हैं जिसमें 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को निगम के साथ सहयोग करना चाहिए और अपना साथी बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने डीजल की सवा दो सौ बसें चलाई हैं। शीघ्र ही 250 नई बसें निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को गत दो वर्षों में कई वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। कर्मचारियों को ओ.पी.एस. तथा रूके हुए भत्तों का लाभ दिया गया है। प्रदेश में आवश्यकतानुसार नए बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वोल्वो की इन बसों के संचालन के उपरांत प्रदेश की आय में बढ़ौतरी होगी तथा स्थानीय लोगों व पर्यटकों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन एवं उद्योग आर.डी. नजीम, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# वर्ष भर बनेंगे हिमकेयर कार्ड

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों के लिए हिमकेयर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5.80 लाख लोगों को उपचार प्रदान करने में लगभग 810 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। हाल ही में, सरकार ने हिमकेयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके हिमकेयर योजना को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार, हिमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में बनाए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में इन कार्डों के महत्व के दृष्टिगत विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और चिकित्सा अधीक्षकों को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय हिमकेयर कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। यह निर्णय जुलाई, 2025 के बाद लागू होगा। यह पोर्टल जुलाई माह में खुला है और लोग इस महीने के दौरान कभी भी हिमकेयर कार्ड बना सकते हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दुर्घटना पीड़ितों को नि:शुल्क उपचार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से दुर्घटना पीड़ितों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त उपचार मिल सकेगा और इसके लिए पैसे, बिल क्लीयरेंस या किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्ड एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे और आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रत्येक तीन माह बाद खोला जाएगा। पोर्टल हर वर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में प्रत्येक तिमाही में एक माह के लिए खुला रहेगा।

लोग पूरे वर्ष हिमकेयर कार्ड का नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। यदि लाभार्थी नीति के अनुसार समय पर कार्ड का नवीनीकरण करवाने में विफल रहता है और उसका कार्ड समाप्त हो जाता है, तो नई नीति के अनुसार समाप्त हो चुके कार्ड का नवीनीकरण मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में किया जा सकेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय पात्र लाभार्थियों के चयन को सुनियोजित करने और लोगों को निर्बाध, नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर अपने कार्ड का नवीनीकरण करवाने के लिए लिया गया है। हिमकेयर कार्ड बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी-फड़ी वालों, अनाथों और जेल के कैदियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए नि:शुल्क बनाया जाता है। एकल महिलाओं, अनुबंध व आउटसोर्स कर्मचारियों, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों, मिड-डे-मील वर्करों, अंशकालिक श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों से इन कार्डों के लिए 365 रुपये लिए जाते हैं। शेष पात्र वर्गों से 1,000 रुपये शुल्क लिया जाता है।

प्रदेश में 5.26 लाख हिमकेयर कार्ड धारक परिवार हैं। इस कार्ड के तहत एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को कवर किया जाता है। हिमकेयर योजना के तहत कुल 3,227 बीमारियों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है। प्रदेश सरकार के 136 स्वास्थ्य संस्थान, जिनमें पीजीआई चंडीगढ़, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंडीगढ़ और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (टाटा मेमोरियल सेंटर), न्यू चंडीगढ़ हिमकेयर लाभार्थियों को नि:शुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश में कार्यरत सभी निजी संस्थानों में हिमकेयर योजना के तहत डायलिसिस सेवाएं नि:शुल्क दी जा रही हैं।

# सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म आरम्भ

**शिमला/शैल।** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 8.31 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया का डिजिटाईजेशन कर सम्पूर्ण प्रक्रिया के संचालन का आधुनिकीकरण करने हेतु एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 15 जून, 2025 से सभी कल्याण योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आरंभ किए गए हैं।

इस सन्दर्भ में सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan से व नजदीकी लोकमित्र केंद्र से कर सकते हैं ताकि आवेदकों के दस्तावेजों की औपचारिकताओं हेतु कार्यालय आवागमन, अनावश्यक समय एवं खर्च की बचत सुनिश्चित की जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत आवेदकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में वह अपने जिला के जिला कल्याण अधिकारी व सम्बधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु मार्गदर्शन व सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# 2027 में पूरे होंगे हिमाचल में चल रहे 2592 करोड़ के नेशनल हाइवे के काम:नड्डा

**शिमला/शैल।** भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इसमें से 785 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर MoRTH और 569 BRO द्वारा बनाए जा रहे हैं।

नड्डा ने इन कार्यो के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया।

नड्डा ने बताया कि NHAI के अंतर्गत चार बड़े कार्य चल रहे हैं जिसमें से अधिकतम कार्य 2026 एवं 2027 तक पूर्ण हो जाएंगे और बाकी 2028 में होंगे।

चार कामों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कीरतपुर मनाली कॉरिडोर जिसके लिए 7667 करोड़ आवंटित है जिसमें 12 टनल 11.51 किलोमीटर का निर्माण होगा।

कीरतपुर मनाली कुल आवंटन 9452 करोड़, 28 टनल जिनकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी। शिमला मटौर 10208 करोड़ का आवंटन जिसमें 15 टनल कुल टनल लंबाई 13.41 होगी। पठानकोट मंडी कुल आवंटन 1088 करोड़, 13 टनल बनेगी जिनकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर होगी। ध्यान दें कि यह लंबाई केवल टनल के बारे है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि वह दो विषयों के बारे में मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे और चिठी भी लिखेंगे।

एक विषय जितने भी NHAI द्वारा काम चल रहे है उनको उद्योग से बाहर किया जाये क्योंकि उन्हें राज्य प्रदूषण बोर्ड की NOC हर साल लेनी पड़ती है जिसके कारण काम धीमी गति से चल रहा है इसके अंतर्गत क्रेशर तारकोल पिघलाने वाले यंत्र हॉट मिक्सर आते हैं यह सब अस्थाई काम है कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं।

दूसरा विषय ड्रेजिंग का है, व्यास नदी के इर्द-गिर्द इस विषय के बारे में काफी चिंता करने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को इसके बारे जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए।

सुमदो काजा सड़क की सैंक्शन 2024 में मिल गई थी और यह काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है पर राज्य सरकार अभी तक इसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं दे पा रही है अगर यह क्लीयरेंस जल्दी आ जाये तो काम जल्दी चलेगा।

घुमारवीं शाहतलाई रोड को 35 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं और 2026 तक यह सड़क अपग्रेड कर दी जाएगी। यह कार्य सीआईएफ द्वारा करवाया जाएगा और जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा।

जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक उनसे क्या आशा यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मंत्री और NHAI के बीच विवाद पर दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और उसमें भी इस प्रकार की घटना चिंताजनक एवं दुख देने वाली है, हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था किसी ने अपने हाथ में ले ली हो।

नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के बारे में ध्यान नहीं दे रही है पर गलती तो राज्य सरकार की है जो केंद्र से आये पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है।

2021 से 2025 तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ही आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फास्ट्रक्चर मिशन के तहत 360 करोड़ 11 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार केवल 78 करोड़ ही खर्च कर पायी है। इस योजना के तहत प्रदेश में 73 ब्लाक लेबल पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से छः ही बन पाये हैं जबकि 14 के टेंडर हुए हैं। आठ क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होने हैं, जिसमें रोहडू, रिकांगपिओ, घवांडल, टांडा, मंडी अस्पताल व पांवटा साहिब शामिल हैं। प्रदेश को 15वें वित्तायोग से 521 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से केवल 128 करोड़ 62 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को मुख्यमंत्री उनसे मिलने आये थे। उन्होंने जाइका से पैसा दिलवाने का आग्रह किया था जिस पर 30 जून को 1138 करोड़ रुपये केंद्र ने मंजूर किये। इसमें से प्रदेश सरकार को 1024 करोड़ रुपये ग्रांट इन एड दिए गए हैं जबकि शेष राशि सस्ते लोन पर उपलब्ध करवाई गई है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तीन साल में एसडीआरएफ के तहत 1736 करोड़, एनडीआरएफ के तहत 1071 करोड़ और स्टेट डिजास्टर मेटिगेशन फंड के तहत 339 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। हाल ही में गृह मंत्री ने पोस्ट डिजास्टर रिहेब्लिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फंड के तहत 2006 करोड़ रुपये दिए हैं।

## पंडोह डैम में जमा हुई लकड़िया

...पृष्ठ 1 का शेष

मांग की जा रही थी। इसके दृष्टिगत सीआईडी जांच का निर्णय लिया गया है। आपदा पीड़ित लोगों की सहायता में पूरा सरकारी तंत्र दिन-रात कार्य कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि संवेदनशील स्थिति में भी भाजपा ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मामले को उठाया। संकट के समय बीजेपी नेता गैर जिम्मेदाराना ब्यान दे रहे हैं, जो उनके दोहरे चेहरे को लोगों के सामने रख रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे की कभी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई और इस दौरान वनों के अवैध कटान के मामले में दोषियों की जवाबदेही को तय नहीं किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में वन माफिया फल-फूल रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधा डालने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी।

# टैरिफ कटौती को लेकर सेब किसान चिंतित अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

**शिमला/शैल।** पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब पर अनुमानित टैरिफ कटौती पर हिमाचल प्रदेश के सेब बागबानों की चिंता को उठाते हुए किसानों की हरसंभव मदद का आग्रह किया है।

पत्र में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा देश में सेब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का प्रमुख स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश में सेब उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है, जो सालाना लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन है, जो वित्तीय दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपये है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश सेब किसान 5 से 10 बीघा के बीच की छोटी भूमि जोत पर काम करते हैं और वे सेब की खेती को अपनी आय का मुख्य स्रोत मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब किसान अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब पर अनुमानित टैरिफ कटौती को लेकर चिंतित हैं। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार चर्चाओं को देखते हुए, इन किसानों को आशंका है कि किसी भी टैरिफ कटौती से उनकी आजीविका पर सीधा और व्यापक असर पड़ेगा। वर्तमान में, अमेरिका से आयातित सेब की रेड डिलीशियस किस्म पहले से ही हिमाचल प्रदेश के सेब बाजार को प्रभावित कर रही है क्योंकि भारत में उगाये जाने वाले सेब की तुलना में कई संघीय सहायता कार्यक्रमों के कारण इन सेबों की उत्पादन लागत अमेरिका में कम है। टैरिफ में किसी और कमी की स्थिति में, इसका परिणाम आयात शुल्क में भारी कमी के रूप में सामने आएगा, जो पहले से असमान खेल के मैदान को प्रभवित करेगा और हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादन को और प्रभावित करेगा।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा उपरोक्त के अलावा, अमेरिका से सेब के आयात में कीमतों में ऐसी कोई भी कमी न्यूजीलैंड, चिली आदि जैसे अन्य देशों से आयातित सेब की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इससे हिमाचल प्रदेश सहित घरेलू रूप से उगाये जाने वाले सेबों के उत्पादन और विपणन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के उपाय भारत में सेब उगाने वाले राज्यों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में कृषि मजदूर आदि के रूप में लगे लाखों लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सेब उगाने वाले किसानों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुये आपसे आग्रह है कि आप अमेरिका के संबंधित अधिकारियों के साथ टैरिफ कटौती पर बातचीत करते समय इन किसानों और सेब की खेती से आजीविका चलाने वालों के संकट और हितों पर विचार करें।